गरीब मज़दूरों के पैसे से अडानी को उबारने की मोदी सरकार की कोशिश

एम्पलाईज प्रोविडंट फंड ऑर्गेनाजेइशन (ईपीएफओ) मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये बनाई गई एक सरकारी संस्था है जो उनकी भविष्यनिधि (प्रोविडंट फंड) पेंशन व बीमा आदि का प्रबन्धन करती है। इस फंड में मुख्य हिस्सा (करीब 90 प्रतिशत) मज़दूरों द्वारा ही नियोक्ता के जरिये भरा जाता है लेकिन सारे निर्णय सिर्फ 10:1 के करीब पैसे देने वाली सरकार द्वारा ही लिये जाते हैं। कहने को तो इसके बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज में मज़दूर यूनियनों के भी कुछ सदस्य होते हैं लेकिन सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की आज तक उन्होंने शायद ही कभी हिम्मत की हो।

ईपीएफओ की साल 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 में इसके पास कुल 18.30 लाख करोड़ रुपये जमा थे। इसमें 11 लाख करोड़ भविष्य निधि और 6.75 लाख करोड़ रुपये पेंशन फंड के थे। जाहिर है इतनी बड़ी राशि में से कुछ हड़पने के लिये सभी पूंजीपतियों की लार टपकती रहती थी लेकिन 2015 से पहले ईपीएफओ अपने पैसे को शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकता था ताकि मज़दूरों के पैसे को शेयर मार्केट में लूटने से बचाया जा सके। लेकिन 2015 में सरकार ने इसका पांच प्रतिशत पैसा शेयर मार्केट में लगाने की छूट दी जो सीमा सितम्बर 2016 में बढ़ाकर 10 प्रतिशत और मई 2017 में 15 प्रतिशत कर दी गई। जाहिर है यह सब मज़दूरों के हित में कम और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये ज्यादा था। ईपीएफओ की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2022 को इसने लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगाया था जो इसके पास जमा कुल राशि का 8.7 प्रतिशत था। लेकिन साल 2022-23 में इसने मज़दूरों के इस साल जमा हुए 2.54 लाख करोड़ रुपये में से 38,000 करोड़ रुपये यानी लगभग 15 प्रतिशत शेयर मार्केट में लगा दिये।

हिंडनबर्ग, अडानी ईपीएफओ 24 मार्च 2023 को एक अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी दो साल की खोजबीन के बाद जारी की एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर अपने एकाऊंट्स में हेराफेरी करने, आपराधिक धोखाधड़ी और अपने शेयरों की कीमतों को चालाकी से बढ़ाने के आरोप लगाये। रिपोर्ट में अडानी समूह द्वारा मॉरीशस आदि देशों में स्थित मुखौटा (शैल) कंपनियों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने का आरोप भी था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और उनकी बाजार पूंजी 100 अरब डॉलर गिरकर लगभग आधी रह गई। यह सब यहां बताना इसलिये जरूरी है कि 'ईपीएफओ' ने शेयर बाजार में लगायी पूंजी का कुछ हिस्सा अडानी ग्रुप की कंपनियों में भी निवेश कर रखा है।

निवेश हालांकि ईपीएफओ ने शेयर बाजार में सीधा-सीधा किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा रखा बल्कि उसने अपना पैसा 'इटीएफ' यानी 'इन्डेक्स ट्रेडड फंड' के जरिये लगा रखा है। दो तरह के इन्डेक्स हैं-एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से जुड़ा-निफ्टी और दूसरा बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से जुड़ा सेंसेक्स। एनएसई के निफ्टी-50 इंडेक्स में अदानी समूह की दो कंपनियां शामिल हैं-अडानी पोर्ट व सेज और दूसरी अडानी एंटरप्राइजेज। जो भी कंपनी 'इटीएफ' में पैसा लगाती है उसको इन्डेक्स में शामिल सभी कंपनियों में पैसा लगाना होता है बल्कि स्वत: लग जाता है। यानी अगर किसी ने 'इटीएफ' के जरिये निफ्टी-50 में पैसा लगाया तो उसको सभी 50 कंपनियों में पैसा लगाना होगा और यह पैसा उसी रेश्यो (अनुपात) में लगाना होगा जो उस स्टॉक एक्सचेंज ने तय कर रखा है। जैसे कि निफ्टी-50 में यदि अडानी की कंपनी 'वेटेज' दो है तो इटीएफ के जरिये 50 रुपये लगाने वाले हर व्यक्ति को दो रुपया अडानी की कंपनी में लगाने होंगे।

खेला: अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट तो 2015 से ही निफ्टी इन्डेक्स का हिस्सा था। जबकि अडानी एंटरप्राइजेज सितम्बर 2022 में इसका हिस्सा बनी। जाहिर है साल 2022-23 में ईपीएफओ द्वारा शेयर मार्केट में लगाये गये 38,000 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा इस कंपनी में लगा होगा। दिसम्बर 2022 में अडानी एंटरप्राइजेज के एक रुपये के शेयर की कीमत 4190 थी जो 29 मार्च 2023 को 1740 रुपये रह गई। तो स्पष्ट है कि ईपीएफओ के इससे निवेश की कीमत भी 60 प्रतिशत कम रह गई होगी।

'हिंडनबर्ग रिपोर्ट' की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद अडानी की इन दोनों कंपनियों की निफ्टी 50 शेयर इन्डेक्स में अगले छह महीने के लिये बनाये रखा गया है। जबकि फरवरी 2023 में इसके मुख्य कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 68 प्रतिशत गिर कर 1400-1500 के बीच झूल रहे थे।

उपरोक्त सारे विवरण से स्पष्ट है कि ईपीएफओ को 'अडानी पोर्ट' में किये गये निवेश पर 35 प्रतिशत और 'अडानी एंटरप्राइजेज' में किये गये निवेश पर 50 प्रतिशत के करीब घाटा अभी तक हो चुका है। जानकारों के अनुसार ये घाटा 3000 से 4000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। ईपीएफओ अपने मुनाफे से मज़दूरों को प्रोविडंट फंड पर ब्याज और पेंशन देती है। अडानी की कंपनियों में निवेश से हुये घाटे की भरपाई मज़दूरो को मिलने वाली पेंशन व ब्याज से होनी स्वाभाविक है। पिछले साल ही ईपीएफओ ने भविष्यनिधि पर ब्याज की दर घटाकर 8.1 प्रतिशत वार्षिक कर दी थी जो 45 साल में सबसे कम है। उधर ट्रस्टीज के रूप में बैठे मज़दूरों के नुमाइन्दों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। 'द हिन्दू' अखबार में छपी एक रिपोर्ट (27 मार्च 2023) के अनुसार ईपीएफओ संगठन के कई ट्रस्टीज द्वारा अडानी कंपनियों में लगाये गये पैसे और उसमें हुए नुक्सान के बारे में कुछ नहीं पता था। पर उनका मानना था कि 27-28 मार्च 2023 को होने वाली ईपीएफओ की मीटिंग में इसकी चर्चा होगी। लेकिन 27-28 मार्च आकर चली गई, मीटिंग भी हो गई, पर इस विषय पर किसी ने चूं तक नहीं की। मोदी सरकार से डरे बैठे मज़दूर यूनियनों के प्रतिनिधियों की भी मोदी के गहरे दोस्त अडानी के ऊपर सवाल उठाने की या जानकारी लेने की हिम्मत नहीं हुई। गौरतलब है कि यूरोप का एक छोटा सा देश नॉर्वे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले ही अडानी समूह के सारे शेयर बेच कर न केवल घाटे से बचा बल्कि मुनाफ़ा भी कमा गया। सरकार की बदनीयति को समझने वाली अनेकों भारतीय कंपनिया अपने मज़दूरों का पैसा ईपीएफओ में जमा कराने की बजाय खुद अपने ट्रस्ट चलाती हैं।

अडानी समूह की आर्थिक धोखाधड़ी के कारण कई सरकारी उपक्रमों-एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि को भी भारी नुक्सान हुआ है जो अन्तत: जनता को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन मज़दूर प्रतिनिधि मज़दूरों के नुक्सान को रोक सकते थे यदि वे 24 जनवरी 2023 के बाद अडानी के शेयरों में शुरू हुई गिरावट के समय ही ईपीएपीओ का पैसा उसकी कंपनियों से निकलवा देते। लेकिन अडानी को डूबने से बचाने के लिये कटिबद्ध मोदी सरकार जब जनता को सारा पैसा उस पर लूटाने को तैयार बैठी हो तब ईपीएफओ जैसे संगठनों की उसको रोकने की क्या औकात! खुद मज़दूरों का भी एक बड़ा तबका मोदी की हिंदू हृदय सम्राट की छवि का पुजारी है तो न तो मोदी पर सवाल उठेंगे न मज़दूरों के नेताओं पर। मज़दूरों और आम जनता का पैसा अडानी जैसे लुटेरों को बचाने के लिए उनकी सेवा में मोदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहेगा।

23 मार्च-शहीद दिवस

गोरे अंग्रेजों से ही नहीं काले अंग्रेजों से भी आज़ादी पाने के लिए प्रेरित करता रहेगा

सत्यवीर सिंह

'ज़ुल्म-ओ-ज़बर और शोषण-अन्याय के ख़िलाफ़ जंग में जान जाए, तब भी पीछे नहीं हटना', 23 मार्च, शहीद दिवस, हर साल ये पैगाम लेकर आता है। इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी, देश के लाडले सपूतों, क्रांतिकारी अमर शहीदों, भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उनका किरदार इतना विशाल है, कि सोते समाज को भी झकझोरने की कूबत रखता है और जो तटस्थ-निष्क्रिय संवेदनहीन हैं, उन्हें लानत भेजता है। देश शहीद-ए-आज़म भगतसिंह और साथियों की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं ही नहीं चढ़ा रहा, बल्कि उनके लिखे एक-एक हर्फ़ को संजीदगी से पढ़ रहा है, समझ रहा है। देश के मुस्तक़बिल के लिए इससे अच्छी ख़बर नहीं हो सकती, क्योंकि 'आज़ाद' भारत में आज, अंधेरा अंग्रेजों के वक़्त से भी ज्यादा घना और दम-घोटू हो चुका है।

'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की फ़रीदाबाद ईकाई ने भी, कम उम्र के अपने छोटे से संगठन के बूते पर, शहीद दिवस बहुत शिद्दत से मनाया। सभी साथी, आज़ाद नगर स्थित चन्द्रिका प्रसाद सामुदायिक केंद्र पर सुबह 11 बजे इकट्ठे होने शुरू हुए और 11.30 बजे, तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार, हाथों में लाल झंडे, शहीद-ए-आज़म के विचारों के बैनर व झंडियाँ लिए, नारे लगाते सेक्टर 24 औद्योगिक बस्ती की सड़कों से गुजरते हुए, 12 बजे सभा स्थल, वीनस पार्क पहुंचे। कार्यक्रम के लिए मज़दूरों को छुट्टी लेने के लिए कहा गया था, लेकिन विकट आर्थिक परिस्थितियों के चलते आधे से भी कम मज़दूर साथी ही अपनी दिहाड़ी गंवाने का साहस जुटा पाए। मज़दूरों की ज़िन्दगी ऐसी बना दी गई है कि एक दिन भी काम ना मिले, तो चूल्हा नहीं जलता। यही वज़ह है कि लेबर चौक पर खड़ा जो मज़दूर, सुबह 8 बजे अपनी दिहाड़ी 500/ रु बोलता है, 11 बजे के बाद 200/ रु में भी 'हां' बोलने को मजबूर हो जाता है। तलवार की धार पर चलते हुए भी साथियों, हमें, अपने महान शिक्षक, पथप्रदर्शक, प्रिय नेता कार्ल मार्क्स का ये सबक़ हमेशा याद रखना होगा, जो उन्होंने विश्व सर्वहारा के सबसे पहले संगठन, प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाते वक़्त हमें दिया था, ''मज़दूरों की मुक्ति की जंग स्वयं मज़दूरों द्वारा ही जीती जानी है।''

भले जलूस बहुत बड़ा नहीं था लेकिन रास्ते भर, सड़क के दोनों ओर खड़े, सैकड़ों

मज़दूरों ने मुस्कुराते चेहरों से मोर्चे का स्वागत किया, नारों में साथ दिया। वीनस पार्क के एक ओर वीनस फैक्ट्री है और बाक़ी तीनों ओर बड़े-बड़े कारखाने हैं, जिनके मज़दूर लंच करने इसी पार्क में आते है। मज़दूर सभा के टाइम को इसीलिए 12 से 2:30 बजे तक रखा गया था। हमें बहुत ख़ुशी हुई कि कई सौ साथियों ने सभा में शिरकत की। अपने सवाल रखे और सभी भाषणों को बहुत ध्यान से सुना और तालियों से हमारा हौसला बढ़ाया। सभा के दरम्यान और बाद में अनेक औद्योगिक मज़दूरों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किये और ख़ुशी जताई कि एक संगठन मज़दूरों को संघर्ष के लिए संगठित और प्रेरित कर रहा है।

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा की ओर से कॉमरेड्स नरेश, सत्यवीर और श्रीमती कविता ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने अमर शहीद क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदानों के प्रति लाल सलाम प्रस्तुत करते हुए, उनके बताए रास्ते चलने का अहद लेते हुए, बताया कि किस तरह 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' और 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पास होते वक़्त, बहरों को सुनाने के लिए केन्द्रीय असेंबली में बम धमाके हुए थे। मोदी सरकार द्वारा 'लेबर कोड बिल, 2020' तथा 2019 में संशोधित यूएपीए, उन कानूनों से 100 गुना ज्यादा मज़दूर-विरोधी और जन-विरोधी हैं और कहीं वैसी बेचैनी पैदा नहीं हुई। ये साबित करता है कि हमने भगतसिंह को सिर्फ़ रस्मी अंदाज़ में ही याद किया है, उनके लिखे के मर्म को नहीं समझा। गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले 'अँगरेज़' बैठा दिए जाने को मैं आज़ादी नहीं मानूंगा, शहीद-ए-आज़म का लिखा एक-एक लफ्ज़ सही हो रहा है।

शोषण-उत्पीड़न की चक्की, मज़दूरों के आक्रोश से महफ़ूज़ रहे, ये ज़िम्मेदारी निभा रही जमात बिलकुल हमारे जैसी ही दिखती है, इसीलिए आज, जनता के असली दुश्मनों को पहचानना, अंग्रेजों के वक़्त से कहीं ज्यादा दुश्वार हो गया है। लेकिन, सरमाएदारों के ताबेदारों की नंगई, चूँकि, बढ़ती जा रही है, इसलिए धुंध छंटने लगी है। 'देशभक्तों' के काले चहरे साफ़ नज़र आने लगे है। अंग्रेज़ों से बारंबार माफ़ी मांगने, गिड़गिड़ाने और पेंशन पाकर वफ़ादार रहने वाले, आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं!

न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, दिल्ली के साथी एम एम चन्द्रा जी, जो संगठन की शुरुआत से ही, हमारे बुलावे को सम्मान देते हुए, हमारा हौंसला बढ़ाने ज़रूर आते हैं, कार्यक्रम में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थ। हम दिली अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि, हमारे कार्यक्रमों को घोषित समय पर शुरू नहीं कर पाते। आगे ध्यान रखा जाएगा।

'श्रमिक वंचित वर्ग संगठन' के साथी संतोष कठेरिया और साथी ओंकार जी को अपने कार्यक्रम में पाकर हमें बहुत ख़ुशी हुई। दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित पालम से, आप ढाई घंटे की यात्रा कर यहाँ पहुंचे थे। मोर्चे के शुरू से सभा के अंत तक, उन्होंने बहुत सक्रिय भागीदारी की। कॉमरेड संतोष कठेरिया ने अपने उद्बोधन में समझाया कि कैसे आज़ादी आन्दोलन में दो धाराएं मौजूद रही। एक धारा भारत के सरमाएदारों, मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और ब्राह्मणवाद रोग से ग्रस्त थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफ़ाक़ और भगतसिंह की धारा देश के शोषित-पीड़ित वर्ग, मज़दूरों-किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी। आज सभी मज़दूर संगठनों को संयुक्त मोर्चों में काम करते वक़्त आने वाली बाधाओं को दूर करने की ज़रूरत है। 'हमें आपस में चर्चा-डिबेट करते हुए साथ में मिलजुलकर काम करना चाहिए'। हम साथी संतोष जी के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और उससे पूरी तरह सहमत हैं।

कॉमरेड ओंकार जी ने अपने बहुत संक्षिप्त वक्तव्य में शहीद-ए-आज़म भगतसिंह के विचारों पर अमल करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि आज भगतसिंह भी संघियों के निशाने पर हैं। उनकी विरासत को बचाने की ज़िम्मेदारी भी मज़दूर वर्ग को ही निभानी है क्योंकि हम ही भगतसिंह के असली वारिस हैं।

वीनस कर्मचारी यूनियन के साथियों ने सभा के आयोजन में सहयोग किया। बड़ी तादाद में सभा में उपस्थित रहे। इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए और जिन साथियों ने अपने काम से छुट्टी लेकर कार्यक्रम में भागीदारी की, उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करते हुए सभा संपन्न हुई।

मोदी शौचालयों से तो खुले में शौच ही अच्छा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में जगह जगह रखे गए शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं हैं। कारण, इन शौचालयों में न तो पानी की व्यवस्था है और न ही सफाई की। करोड़ों रुपये कीमत के यह शौचालय देखभाल और रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो चुके हैं। विकास के नाम पर नगर निगम और सरकारी विभाग जनता के कर की गाढ़ी कमाई इसी तरह बर्बाद कर रहे हैं लेकिन सरकार को यह नजर नहीं आ रहा।

2014 में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का जुमला दिया था। इसके तहत खुले में शौच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। खुले शौच रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत फरीदाबाद में 1200 शौचालय स्थापित किए गए थे। करोड़ों रुपये कीमत खर्च कर लगाए गए इन शौचालयों में कुछ दिन तक तो पानी और सफाई की गई, उसके बाद इन्हें लावारिस छोड़ दिया गया।

दरअसल, प्रत्येक शौचालय की पानी और सफाई व्यवस्था के लिए कम से कम एक स्वच्छता कर्मी की तैनाती अनिवार्य थी। निगम प्रशासन के पास इतने स्वच्छता कर्मी तैनात

करने का न तो बजट था और न ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनकी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। हुआ यह, कि योजना का खूब ढिंढोरा पीटा गया और खुले में शौच करने वालों पर उत्साहपूर्वक जुर्माना लगाकर उन्हें हतोत्साहित किया गया। मजबूरी में लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल तो करने लगे लेकिन सफाई नहीं होने के कारण इनमें शौच करना मुश्किल हो गया।

दो अक्तूबर 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृष्णानगर मलिन बस्ती में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का ड्रामा करते हुए फोटो खिंचाई थी।

इस बस्ती के पास भी शौचालय लगाया गया। मैदान में झुग्गियां डाल कर रहने वाले लोगों ने बताया कि इन शौचालयों में कभी सफाई ही नहीं की गई। कुछ दिन तो पानी की व्यवस्था की गई लेकिन करीब छह साल से वह भी बंद है। इन गंदे और बदबूदार शौचालयों में जाने से तो अच्छा है खुले में शौच करना, यह तो बीमारियों की जड़ हैं।

सैक्टर 21 सी मार्बल मार्केट में भी करीब सात वर्ष पहले लगाए गए शौचालय तो कभी शुरू ही नहीं हुए। इनमें न तो पाइप का कनेक्शन दिया गया और न ही ताला खोला गया। इस्तेमाल किए बिना ही यह शौचालय जर्जर हो गए। सभी 1200 शौचालयों की हालत इसी तरह जर्जर है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री बताते हैं कि शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थापित किए गए बारह सौ शौचालयों में कोई सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है। उन्हें छोड़ भी दिया जाए तो नगर निगम में सफाई कर्मियों के स्वीकृत पद भी खाली पड़े हैं।

शहर की सफाई व्यवस्था के जिम्मेदार नगर निगम के एक्सईएन पद्मभूषण ने शौचालयों की अव्यवस्था के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। एक्सईएन बेचारा बताए भी तो क्या उसके पास है ही क्या बताने को।